अध्ययन ◆ गांवों में खाद्य वस्तुओं पर खर्चा घटा लेकिन गैर खाद्य वस्तुओं पर खर्चा शहर के बराबर नहीं

शहरी से एक दशक पीछे ग्रामीण बाजार

इसमें कोई शक नहीं कि पिछले दो दशकों में उपभोक्ताओं की पसंद और प्राथमिकता काफी खुल कर सामने आई है। हालांकि उपभोक्ता पसंद को शक्ल देने और इसकी एक साफ तस्वीर उभारने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं की तरह विभाजन बहुत साफ नहीं दिखता। लेकिन इसे बताने की जरूरत है। इसी तरह शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के संबंध और शहरी उपभोक्ताओं का ग्रामीण उपभोक्ताओं पर असर का आकलन भी जरूरी है। ग्रामीण इलाकों से शहर में जा कर बस जाने वाले उपभोक्ताओं की पसंद में परिवर्तन पर भी गौर करना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि शहरीकरण से परिवारों में उपभोग का पैटर्न किस तरह से बदल रहा है? सबसे पहले तो शहरीकरण से खान-पान की आदतों में बदलाव आ सकता है। इससे इन चीजों मांग में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। इस तरह के बदलाव की वजह से परिवार भी जीवनशैली बदल लेते हैं। हालांकि इन बदलावों के बारे में बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं हैं।

दरअसल उपभोग की आदतें दो तरह की वजहों से प्रभावित होती हैं। पहली वजह आंतरिक होती है। मसलन जीवन मूल्यों, प्रवृतियों, संस्कृति और आदि में परिवर्तन उपभोक्ताओं की प्राथमिकता और पसंद में बदलाव कर सकते हैं। बाहरी कारणों में खर्च की जाने वाली आय, समय की उपलब्धता और परिवार के स्वरूप जैसे तत्व शामिल हैं। इन वजहों से ही किसी उपभोक्ता की क्षमता निर्धारित होती है और इस वजह से ही वह अपनी प्राथमिकता या पसंद पूरी करता है।

भारत में आंकड़ों के ज्ञान का इतिहास और समृद्ध परंपरा रही है लेकिन मौजूदा प्रणाली भारत में उभरते आर्थिक और सामाजिक बदलावों को आत्मसात करने में पूरी तरह सफल नहीं दिख रही है। बहरहाल अपनी तमाम खामियों के बावजूद नेशनल सैंपल सर्वे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आंकड़ों की कमी वाले इस देश में ये सर्वे काफी समृद्ध जानकारियां देते हैं।

बहरहाल गुणवत्तापूर्ण शोधों से यह साबित हो चुका है कि आमदनी बढ़ते ही परिवारों में खाने-पीने के आइटमों पर खर्च घटने लगता है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में होता है। यह तथ्य पूरी तरह एंजेल्स के नियम की पुष्टि करता है।

लेखक एनसीएईआर में मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च के डायरेक्टर हैं। ग्रामीण और शहरी बाजारों में खर्च के पैटर्न पर उनका लेख।

राजेश शुक्ला

सार्वजनिक तौर पर मौजूद आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कई चौंकाने वाले तथ्य नजर आते हैं। वर्ष 1993-94 और 1999-2000 के बीच शहरी क्षेत्रों में उपभोग के आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि शहरी उपभोक्ता एक दशक पहले खाने-पीने की चीजों पर जो खर्च करता है, उससे अब कम खर्च करने लगा है। इसके बदले गैर फूड आइटमों पर खर्च बढ़ा है।

दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को अभी इस स्तर को हासिल करना है। इस एक दशक के दौरान इन परिवारों का भोजन से जुड़े आइटमों पर खर्च तो घटा है लेकिन अभी भी गैर फूड आइटमों की तुलना में इनकी खपत ज्यादा है। लेकिन अगले कुछ सालों में यह फासला कम हो रहा है और आने वाले सालों में फूड आइटमों का तुलना में गैर फूड आइटम पर खर्च बढ़ सकता है। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विभिन्न श्रेणियों में खर्च का वितरण कुल खर्च के फीसदी के तौर पर दिखाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है किग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनाजों पर खर्च का हिस्सा घटा है।

ग्रामीण इलाकों में 1987-88 में अनाजों पर खर्च उपभोक्ता के खर्च का 26 फीसदी था जो 2009-10 में घट कर 16 फीसदी हो गया। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 1987-88 में अनाज पर उपभोक्ताओं का खर्च 15 फीसदी था लेकिन 2009-10 में यह घट कर नौ फीसदी हो गया। यानी इसमें सीधे छह फीसदी की गिरावट दर्ज की गई । लेकिन यह बताना जरूरी है कि इस बीच ग्रामीण इलाकों में पेय पदार्थों पर खर्चा बढ़ा है। 1987-88 में ग्रामीण इलाके में उपभोक्ता के खर्च का चार फीसदी पेय पदार्थों पर होता था लेकिन 2009-10 में यह बढ़ कर छह फीसदी हो गया।

संजय डिमरी

इस दशक के दौरान जिन गैर फूड आइटमों पर खर्च बढ़ा है उनमें शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, कंज्यूमर सर्विस, छोटे उपभोक्ता सामान, प्रसाधन और दूसरी सामग्री शामिल हैं। इन्हें अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणियों में शामिल किया गया है। इस तरह की चीजों पर खर्च काफी बढ़ गया है और ग्रामीण इलाके के उपभोग बास्केट में 2009-10 इनकी हिस्सेदारी बढ़ कर 24 फीसदी हो गई है जबकि इसी अवधि में शहरी आबादी में यह बढ़ कर 38 फीसदी हो गया है।

यहां यह भी प्रासंगिक है कि ग्रामीण इलाकों में अनाजों पर होने वाले खर्चों में गिरावट की भरपाई अन्य वस्तुओं और सेवाओं की श्रेणी में शामिल चीजों पर होने वाले खर्च से हो गई। जिन अन्य श्रेणियों में खर्चा बढ़ा वह हैं इस्तेमाल की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं, ईंधन और बिजली। ग्रामीण इलाकों में ईंधन और लाइट पर होने वाला खर्चा कुल खर्चे का दस फीसदी है। जबकि रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों की इसमें भागीदारी पांच फीसदी है। यहां यह दिलचस्प है कि ग्रामीण इलाके के उपभोक्ता शहरी उपभोक्ताओं की तुलना में ईंधन और लाइट (बिजली) का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 1987-88 में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता इस पर सात फीसदी खर्च कर रहे थे लेकिन 2009-10 में यह महज एक फीसदी बढ़ा और आठ फीसदी हो गया।

इन परिवर्तनों से यह समझना जरूरी हो गया है कि खाने-पीने की आदतों और जीवनस्तर के विकल्प के बारे में उपभोक्ताओं का नजरिया किस कदर बदला है। इस तरह की जानकारियों से इस क्षेत्र में सक्रिय उद्योगों को आगे आने वाली चुनौतियों और उपभोक्ताओं की बदलती मांग और पसंद के मुताबिक खुद को ढालने में मदद मिलेगी। क्योंकि उद्योगों के लिए प्राथमिकताएं और निवेश मांग के आकलन और रुख पर निर्भर करती हैं। अगर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के बीच उपभोग के पैटर्न को समझना है तो आय से जुड़े आकलन की भूमिका अहम हो जाती है। इस तरह के अध्ययन से बहुस्तरीय भारतीय उपभोक्ताओं को समझने में काफी मदद मिलती है।